G7 शिखर सम्मेलन

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक समूह, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

संदर्भ

- भारत और जर्मनी के बीच सुदृढ़ और घनिष्ठ साझेदारी और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा के दृष्टिगत जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के विशेष निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26-27 जून को जी 7 शिखर सम्मेलन के लिए श्लॉस एलमौ (जर्मनी) की यात्रा करेंगे।
- G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 जून, 2022 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करेंगे।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- विदित है कि भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) के छठे संस्करण के लिए पीएम मोदी की अंतिम जर्मनी यात्रा 2 मई, 2022 को हुई थी।
- प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन दिवसीय यूरोप यात्रा के पहले चरण में जर्मनी में थे।
- जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था।
- दिसंबर 2021 में चांसलर स्कोल्ज के पदभार ग्रहण करने के बाद से यह उनकी पहली भेंटवार्ता थी।

भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) का छठा संस्करण

- संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, छठे अंतर-सरकारी परामर्श के दौरान भारत और जर्मनी ने हरित और सतत विकास के लिए अपने समझौते में हाइड्रोजन रोडमैप विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देश भारत-जर्मन अक्षय ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने पर सहमत हुए, जिसमें नवीन सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जिसमें बिजली ग्रिड, भंडारण और बाजार डिजाइन के लिए संबंधित चुनौतियों को शामिल किया गया, ताकि एक उचित ऊर्जा संक्रमण की सुविधा मिल सके।
- मई में यात्रा के दौरान, भारत और जर्मनी ने सतत विकास पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो भारत को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करने के लिए 2030 तक € 10 बिलियन की सहायता प्रदान करेगा।
- उस समय, स्कोल्ज़ ने भारत को "अर्थव्यवस्था, रक्षा और जलवायु नीति के मामले में एशिया में जर्मनी के लिए केंद्रीय भागीदार" के रूप में वर्णित किया।

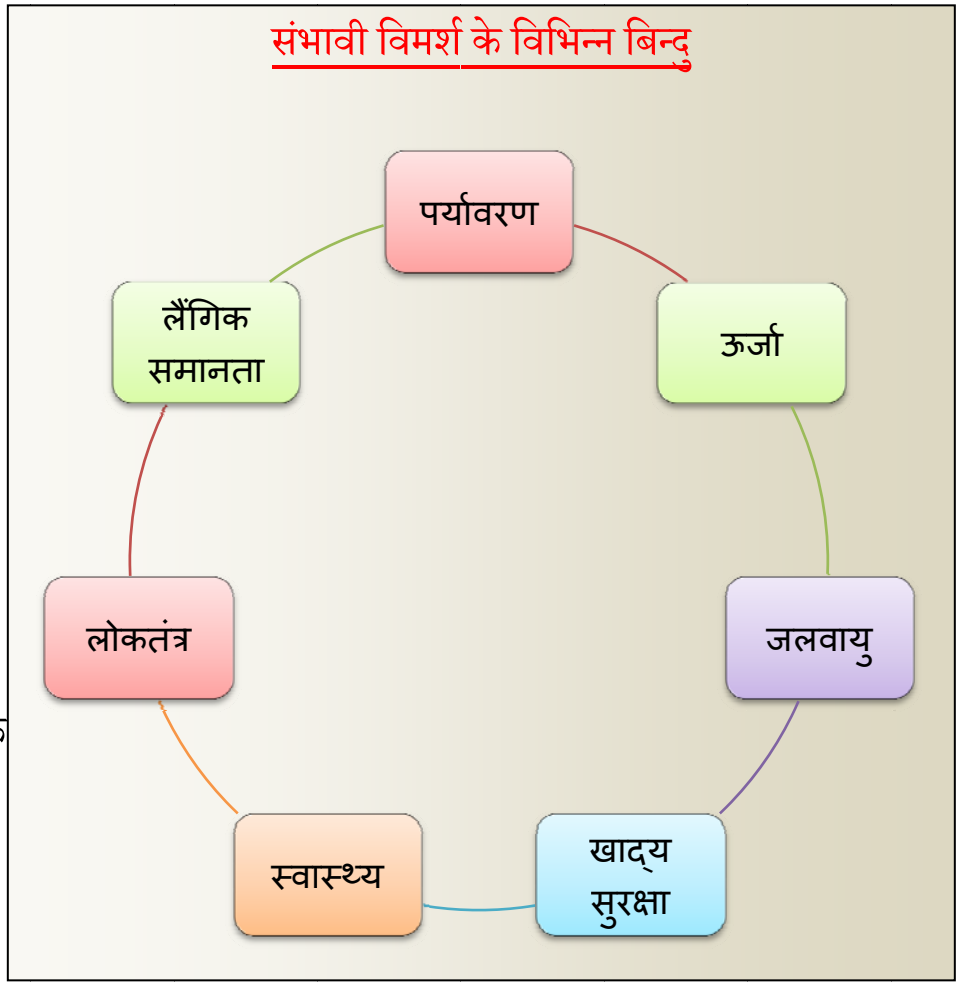

आमंत्रित देश

- प्रधानमंत्री जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के निमंत्रण पर जर्मन रिसॉर्ट श्लॉस एल्मौ की यात्रा करेंगे। उनके दो सत्रों में बोलने की संभावना है, जो पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र पर केंद्रित होंगे।
- भारत के अलावा, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और सेनेगल जैसे देशों को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।

भारत को क्यों आमंत्रित किया गया है?

- भारत को प्राप्त जी-7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भारत और जर्मनी के बीच मजबूत और करीबी साझेदारी और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है।
- प्रधानमंत्री को जी 7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण यूक्रेन में संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत को रूस से दूर करने के जर्मनी के प्रयासों का हिस्सा है।
- विदित है कि रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों के कारण भारत ने यूक्रेन संकट पर तटस्थ रुख बनाए रखा है और बार-बार शत्रुता को समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है।

जी 7

क्या है?

- जी 7 सात देशों का एक अनौपचारिक समूह है।
- यह यह विश्व की सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- रूस को 1998 में शामिल करते हुए जी 8 का निर्माण किया गया, किन्तु 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के कारण इसे बाहर कर दिया गया।

सदस्य देश

- इसके सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम हैं, जो यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं।
- विदित है कि यूरोपीय संघ जी 7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।

वैश्विक प्रतिनिधित्व

- सदस्य देश मिलकर वैश्विक जीडीपी का 40% और दुनिया की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्या G7 के पास कोई शक्ति है?

- यह कोई कानून पारित नहीं कर सकता, क्योंकि यह अलग-अलग राष्ट्रों से बना है, जिनकी अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं।
- यद्यपि, इसके पिछले कुछ निर्णयों का वैश्विक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, जी 7 ने 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूके में 2021 में होने वाले जी 7 शिखर सम्मेलन से पहले, जी 7 के वित्त मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक कर देने पर सहमत हुए। इसने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को संबोधित किया है।

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक का प्रतिनिधित्व करेगा

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- ब्रिक्स व्यापार फोरम को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लिखित किया कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कुल 2.5 ट्रिलियन डॉलर की क्षमता है।
- साथ ही, भारत ड्रोन, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में नवाचार का समर्थन करता है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

14वां ब्रिक्स सम्मेलन

- चीन में 23 जून से 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है।
- दो दिन की इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग की स्थिति और उनकी संभावनाओं पर विमर्श करेंगे।
- वर्तमान अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों की समीक्षा करने की भी योजना है।
- ज्ञातव्य है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

14वां ब्रिक्स सम्मेलन और भारत

- विदेश मंत्रालय के अनुसार, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा 24 जून को मेहमान देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्चस्तरीय संवाद में भी हिस्सा लेंगे।

13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

- 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पिछली बार भारत में हुआ था।
- विदित है कि 2012 और 2016 के बाद तीसरी बार भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।
- बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।

ब्रिक्स व्यापार फोरम में भारत के संबोधन के मुख्य अंश

- भारत की सफलता का आधार नवाचार और स्टार्टअप्स के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का विकास भी है।
- अंतरिक्ष, नीली अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा, ड्रोन और भू-स्थानिक डेटा जैसे क्षेत्रों में उभरते नए भारत में हर क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कुल 2.5 ट्रिलियन डॉलर की क्षमता है।
- भारत में जो डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, वह विश्व मंच पर पहले कभी नहीं देखा गया।
- भारत में 70,000 से अधिक स्टार्ट-अप में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
- नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश के अवसर हैं।

निम्नलिखित क्षेत्रों में नवाचार समर्थन का उल्लेख किया गया :

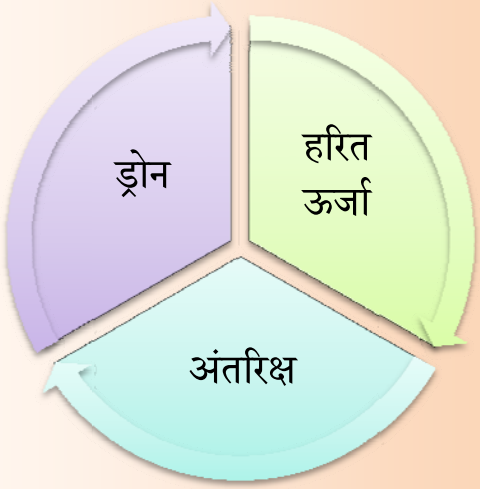

- भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य 2025 तक $ 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा।
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम के जरिये आधारभूत संरचना को तैयार करने और डिजिटल सुधार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण का कार्य पूरा किया गया।
- महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने सुधार कार्य और परिवर्तन जैसे तरीकों का प्रयोग किया। यह भारत की आर्थिक सोच का परिणाम है।

- ध्यातव्य है कि ब्रिक्स संगठन की स्थापना इस विश्वास के साथ की गई थी कि ये समूह वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन होगा। आज जब पूरा विश्व कोविड के बाद की स्थिति को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किए हुए है, ऐसी स्थिति में ब्रिक्स में शामिल देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।

ब्रिक्स

क्या है?

- ब्रिक्स को विश्व की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन के रूप में जाना जाता है।
- यह विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में विदित है।

सदस्य देश

- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका

पृष्ठभूमि

- ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी।
- विदित है कि प्रारम्भ में इसमें चार देश (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) शामिल थे, जिससे इसका नाम ब्रिक (BRIC) था।
- वर्ष 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम BRIC से बदलकर BRICS हो गया।
- वर्ष 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था।

उद्देश्य

- ब्रिक्स (BRICS) संगठन एक बहुपक्षीय मंच है, जिसमें दुनिया की 5 अहम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
- यह विश्व की जनसंख्या का 41 फीसदी, वैश्विक जीडीपी का करीब 24% और विश्व व्यापार के 16% भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- ब्रिक्स समिट में क्षेत्रीय मुद्दों के साथ वैश्विक मामलों पर भी चर्चा होती है। इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में सदस्य राष्ट्रों के बीच पारस्परिक लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाना है, ताकि इनके विकास को गति मिल सके।
- इसमें जलवायु परिवर्तन (Climate Change), आतकंवाद (Terrorism), विश्व व्यापार, ऊर्जा, आर्थिक संकट आदि जैसे विश्व महत्व के मुद्दों को संबोधित किया जाता है।

स्रोत: द हिन्दू, हिंदुस्तान टाइम्स